विदेशों के समाचार-पत्रों के लोग ही नहीं, हमारे समाचार-पत्र भी यही कर रहे हैं। मैं जब समाचार-पत्र में काम करता था, तब मैं भी यही करता था।

अध्यक्ष महोदय, कुत्ता आदमी को काटे यह खबर नहीं, मगर आदमी कुत्ते को काटे तो यह खबर अच्छी लगती है। मगर हमने विदेशी दूतावासों को कहा है कि वह प्रचार के तंत्र को अधिक सक्षम और प्रभावी बनावें। मैं आशा करता हूं कि थोड़े दिनों में परिणाम सामने आयेंगे।

श्री हुकम देव नाराण यादव : जहां तक भारत के बारे में गलत प्रचार विदेशों में होता है, वह रोका जाना चाहिये। लेकिन अगर भारत की सही तस्वीर विदेशों में दिखलाई जाती है जो कि गांवों में लोगों की स्थिति है, उनकी जो हालत है आर्थिक व सामाजिक शोषण से, और विदेशी कर्जा लेकर देश के विकास के नाम पर इतने दिनों तक खर्चा किया गया और देश का विकास हो नहीं पाया।

MR. SPEAKER: You are going completely out of the question.

श्री हुकम देव नारायण यादव : अगर इन बातों को विदेश वाले दिखाते हैं, और कहते हैं कि भारत का विकास नहीं हुआ है और विदेशी सहायता का सही उपयोग नहीं हुआ है, तो उस में क्या ग़लती है ?

MR. SPEAKER: It does not arise out of this.

Number of Unemployed and Payment of Unemployment Allowance

*44. SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA:

SHRI K. MAYATHEVAR:

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) the number of persons registered at all employment exchanges on first January of 1975, 1976, 1977 and 1978 and how many of the registered were unemployed;

(b) what is Government's estimate of all unemployed persons who have not registered at employment exchanges and what are the reasons for their not registering at employment exchanges; and

(c) what is the estimated expenditure likely to be incurred if all those registered at employment exchanges were paid a minimum subsistence monthly unemployment allowance?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KIRPAL SINHA): (a) The number of persons on the Live Register of Employment Exchanges as on 31st December, of 1974, 1975 1976 and 1977 was of the order of 84.33, 93.26, 97.84 and 109.24 lakhs respectively. The number of unemployed persons amongst the registered is not available.

(b) As per the 27th round of the National Sample Survey conducting during 1972-73, the percentage of unemployed persons who have not registered at the Employment Exchanges was about 65 (provisional). Registration being voluntary all the unemployed persons need not register with the employment exchanges.

(c) Payment of unemployment allowance to the unemployed is not considered practical in the present state of the economy. Hence, the estimate of expenditure likely to be incurred it all those registered at Employment Exchanges are paid a minimum subsistence monthly unemployment allowance would be hypothetical.

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : : मंत्री महोदय ने बताया है कि दिसम्बर, 1977 में 109 लाख लोगों के नाम एम्पलायमेंट एक्सचेंजों में दर्ज थे, और यह भी कि 65 परसेंट लोग अपने नाम एम्पलायमेंट एक्सचेंजों

में दर्ज नहीं कराते हैं । इस के मुताबिक इस समय देश भर में तीन, चार करोड़ के करीब लोग बेकार हैं । जनता पार्टी ने यह वादा किया है कि दस साल में इस देश में बेकारी दूर कर दी जायेगी । चार करोड़ के करीब लोग इस समय बेकार हैं, और हर साल पचास लाख नये लोग बेकारों की श्रेणी में बढ़ते जा रहे हैं । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस विस्फोटक स्थिति, एक्सप्लासिव सिचुएशन, से निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है और इस बारे में उस के क्या प्लान्ज हैं ।

डा० राम कृपाल सिंह : : सरकार अनएम्पलायमेंट की स्थिति की गम्भीरता को समझती है, और इस लिए उस ने एक समय-बद्ध कार्यक्रम तय करने का निश्चय किया है कि अगले नौ, दस वर्षों में इस समस्या का समाधान ढूंढा जाये । इस हेतु कई तरफ़ से इस समस्या पर प्रहार किया जायेगा । ग्रामीण क्षेत्रों में हम कृषि पर ज्यादा ज़ोर देना चाहते हैं और उस के लिए एलोकेशन्ज बढ़ा रहे हैं । कृषि, सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, कृषि से सम्बन्धित उद्योगों, लघु उद्योगों और गृह उद्योगों आदि योजनाओं से यह सम्भव है कि इस समस्या का समाधान निकल पाये ।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : सरकार के मुताबिक हर वर्ष पचास लाख नये लोग बेकार होते हैं, और पुराने बेकार भी हैं । इस के लिये साल में एक करोड़ एडीशनल जाब्ज क्रीएट करने की जरूरत है । मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर दस साल में बेकारी को दूर करना है, तो एक साल में एक करोड़ जाब्ज पैदा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है । मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार इस समय कोई अनएम्पलायमेंट डील नहीं दे सकती है । वह कोई बेकारी भत्ता नहीं दे सकती है, लेकिन जनता पार्टी ने यह वादा किया है कि वह दस सालों में इनकम की रेशो 1 और 10 तक ले जायेगी । इस वक्त बेकारों की इनकम ज़ीरो पर है । तो फिर इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ? हम ने अपने कांस्टीट्यूशन में राइट टू वर्क की बात कही है, और अपने मैनिफ़ैस्टो में भी उस का वादा किया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या कदम उठा रही है ।

डा० राम कृपाल सिंह : जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, सरकार जो छठी योजना का प्रारूप तैयार कर रही है, उस में सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि कोई एड हाक निर्णय लिया जाये—जैसा कि किसी ज़माने में हाफ ए मिलियन जाब्ज का नारा दिया गया था; हम नारेबाज़ी में विश्वास नहीं करते हैं—कि एक साल में हम इतने लोगों को नौकरियों में भर्ती कर रहे हैं । सरकार की योजना ज्यादा से ज्यादा जाब अपार्च्युनिटीज और ज्यादा से ज्यादा सेल्फ एम्पलायमेंट अपार्च्युनिटीज क्रियेट करने की है और इस तरह से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए 8 सेक्टर तय किए गए हैं—

Textiles, sugar, rice and oil-milling, wood products building material and metal fabrication.

इस तरह भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से और भिन्न भिन्न तरह से प्रहार कर के हम इस समस्या का समाधान कर रहे हैं ।

SHRI. K. MAYATHEVAR: Mr. Speaker, Sir, I want to know from the hon. Minister the total number of persons unemployed from the educated category and uneducated category and what steps are taken to provide employment for these two catgories.

DR. RAM KRIPAL SINHA: Up to June, 1977, the total number of educated unemployed on the live registers is 53, 90, 592.

MR. SPEAKER: And what steps are you proposing to take?

DR. RAM KRIPAL SINHA: As I have already said, when we create more job opportunities in small-scale and cottage industries and tiny indutries, that will solve the problem. As I said in the begining we do not believe in any ad hoc slogans like Half-a-million jobs etc.

श्री फिरंगी प्रसाद : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं और यह मेरा निश्चित प्रश्न है कि जनता पार्टी को शासन में आए एक साल के लगभग हो रहा है, इस बीच कितने लोग सेवा से निवृत्त हुए, उन की जगह कितनी भर्ती की गई और उन में कितने नये लोग लिए गए ?

MR. SPEAKER: That does not arise.

SHRI HITENDRA DESAI: From the replies given it appears that since the Janata look over, about 20 lakhs of educated unemployed has grown. Will the Government think of giving some guarantee to the right to work?

DR. RAM KRIPAL SINHA: As far as the question of giving guarantee to the right to work is concerned, we believe that the first phase is to create a realistic situation where even if we give the right to guarantee the job, that can be fulfilled. There is no sense in giving a guarantee without providing opportunities for fulfilling the guarantee.

श्री छबिराम अर्गल : मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि शिक्षित बेरोजगारों के नाम तो रोजगार कार्यालयों में पंजीबद्ध हैं लेकिन ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो अशिक्षित बेरोजगार हैं उन के नाम वहां पंजीकृत नहीं किए जाते हैं, क्या सरकार अशिक्षित बेरोजगारों के लिए कोई योजना बनाएगी और जैसा कि चुनाव के घोषणा-पत्र में कहा गया था कि शिक्षित बेरोजगारों को अगर रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो अभी तक क्या कुछ लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया है या देने की योजना है ?

डा० राम कृपाल सिंह : एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज में पंजीकरण बिल्कुल ऐच्छिक है । जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी वहां पर पंजीकरण कराने का अधिकार हैं । यदि माननीय सदस्य ऐसे लोगों की मदद करके उनका पंजीकरण वहां पर करा दें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

जहां तक माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, उसका मैं पहले ही जबाब दे चका हूं ।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी को मालूम है, हर वर्ष विश्वविद्यालयों से निकलने वाले बेरोजगार युवको की संख्या 50 लाख होती है । हर वर्ष इतनी संख्या बेरोजगारों की संख्या में जुड़ती जाती है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनता सरकार ने दस साल में बेरोजगारी दूर करने का नारा दिया है जिसमें एक वर्ष बीत गया है और रोजगार देने के लिए जो आयु सीमा लगा रखी है उसमें जिन को रोजगार नहीं मिलेगा और वे उस आयु सीमा को पार कर जायेंगे तो क्या उनके लिए सरकार आयु सीमा को बढ़ाने के लिए विचार कर रही है ?

डा० राम कृपाल सिंह : देश में जो बेरोजगार हैं उन सभी को सरकारी नौकरियों में जगह देना कहां तक सम्भव होगा यह माननीय सदस्य स्वयं समझ सकते हैं और आयु सीमा केवल सरकारी नौकरियों के लिए है परन्तु अनेक ऐसे प्राइवेट सेक्टर हैं और ऐसी जाब्स हैं जिनके लिए आयु सीमा नहीं है ।

श्री बिनायक प्रसाद यादव : अभी तक एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज के जो दफ्तर हैं वह शहरों में हैं और गांवों के लोग उनमें अपना

नाम दर्ज नहीं करा पाते हैं । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी लाइव रजिस्टर पर जो अनएम्पलायड लोग हैं उनमें कितने निरक्षर दर्ज हैं और कितने साक्षर दर्ज हैं ?

डा० राम कृपाल सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज नहीं हैं लेकिन जिला केन्द्रों में एम्पलायमेंट एक्सचेंज हैं और जिला केन्द्रों के लिए यातायात की सुविधायें हैं देहात के लोग शहरों में आते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं । अभी जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार मैट्रीकुलेट और उससे ऊपर की योग्यता के लोगों की संख्या 53 लाख 90 हजार है लेकिन बाकी कितने भी हैं वे नान-मैट्रिक या उससे भी नीचे के हैं जिनमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जोकि साक्षर न हों ।

National Tripartite Conference on Agricultural Labour

+

*46. SHRI S. G. MURUGAIYAN:

SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV:

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether a national tripartite conference on agricultural labour was convened by him from 24th January, 1978;

(b) if so, the main issues discussed therein and with what results; and

(c) what was the criteria of inviting representatives to this conference?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय): (क) जी हां ग्रामीण असंगठित श्रमिक सम्बन्धी विशेष सम्मेलन 25 जनवरी 1978 को हुआ था ।

(ख) और (ग) . विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

(ख) और (ग) : निर्धन ग्रामीणों का संगठन—ग्रामीण श्रमिक संगठनों के समुचित विकास के लिए सुझाव और (ii) खेतिहर श्रमिकों के रोजगार और कल्याण की सुरक्षा के लिए एक व्यापक विधान की आवश्यकता ।

2. सम्मेलन ने ग्रामीण श्रमिक संगठनों के विकास और ग्रामीण श्रमिकों के कार्य तथा जीवन की दशाओं से सम्बन्धित मामलों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए ग्रामीण असंगठित श्रमिक सम्बन्धी केन्द्रीय स्थायी समिति का गठन करने का निर्णय किया है । यह निर्णय किया गया था कि ग्रामीण श्रमिक की परिभाषा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय-141 में दी गई परिभाषा के अनुरूप होनी चाहिए । सम्मेलन में खेतिहर श्रमिकों के बारें में केन्द्रीय विधान बनाने के पक्ष में मतैक्य था । सम्मेलन में इस बात पर भी मतैक्य था कि सेवा की सुरक्षा; कार्य घण्टों का विनियमन; मजदूरी दरों का निर्धारण/संशोधन; समाज सुरक्षा उपायों और विवादों के निपटान के लिए मशीनरी के बारे में सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए श्रम मंत्रालय आगे कार्यवाही करे ।

व्यापक परामर्श करने के लिए कुछ ऐसे संस्थानों/संगठनों को आमंत्रित किया गया था जो यह समझा जाता है इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं । निम्नलिखित को आमंत्रित किया गया था:—(1) राज्य सरकारें- (2) सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालय जैसे कृषि मंत्रालय ग्राम विकास विभाग, (3) ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिक संगठन (केन्द्रीय श्रमिक संगठनों सहित), (4) ग्रामीण श्रमिकों की समस्याओं में रुचि रखने वाले स्वैच्छिक संगठन/संस्थान व्यक्ति, (5) कृषि मंत्रालय द्वारा सुझाए